DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022 ----------DATED----------

Not just fast travel, RRTS to offer studio apartments for short stays

Flats In Jangpura To Provide Various Facilities, Can Be Booked On Portals

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Apart from covering 82km between Meerut and Delhi in less than an hour for the convenience of commuters, the Regional Rapid Transit System (RRTS) corridor also promises fully-serviced studio apartments in south Delhi's Jangpura for people planning a short stay in the capital.

The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC), which is executing the RRTS project, is constructing studio apartments in a 15-floor building close to the Jangpura RRTS station. It has invited expression of interest (EOI) from serviced apartment operators.

Initially, NCRTC will develop 149 units, including 96 studio apartments and some single-bedroom apartments. While the studio apartments will have an area of 45.7 sq metres, the 1bhk flats would span 81sq metres.

The studio apartments are aimed at visitors coming to Delhi for official or personal work and who need to stay in the city for a short duration. The Jangpura station will have direct connectivity with Sarai Kale Khan station, which will help commuters access not only the Meerut RRTS corridor, but also the two proposed corridors to Panipat and SNB (Shahjahanpur, Neemrana, Behror).

According to EOI, visitors may book these studio apartments through travel portals and should be able to use the fully-furnished flats with cleaning, housekeeping, kitchen, laundry, Wi-Fi, etc, provided as services. The private operator will not only provide services to the renters, but also manage maintenance and other operations such as sales and marketing of the inventory and landscaping of common areas.

While the top 14 floors of the first under-construction tower have studio apartments and 1bhk apartments, the ground floor will offer common amenities like a gymnasium, yoga room, dining area and kitchen, lounge, gaming zone, canteen and laundry room. Recreational spaces like a terrace garden and a lounge are proposed on the tower top.

The tower is coming up on a land parcel measuring around 42.7 acres allotted to NCRTC in Jangpura, which has been notified as a Transit Oriented Development (TOD) node by Delhi Development Authority. The Delhi TOD Policy, 2021, allows a floor area ratio of up to 500 for all TOD schemes.

As part of TOD, the area is going to be developed to maximise the amount of residential, commercial, business and leisure spaces with the convenience of connectivity. As per the current master plan of the area, this includes residential towers and commercial complexes, among other planned connectivity measures.

There are two proposed access roads to the 15-storey building, one from Mathura Road and one from Ring Road. NCRTC is already working on providing connectivity from Mathura Road and the process of engaging a contractor for providing connectivity from Ring Road is in the process. The site is also located close to Delhi Metro's Violet Line (Kashmere Gate-Raja Nahar Singh, Ballabhgarh) and is not very far from the Pink Line (Majlis Park-Shiv Vihar) either.

The construction work on the RRTS corridor is in full swing and the 17-km priority section between Sahibabad and Duhai is scheduled to be commissioned by 2023. The full corridor from Meerut to Delhi is expected to become operational by 2025.

EOI STATES

The visitors may book these studio apartments through travel portals and should be able to use the fully-furnished flats with services

ENHANCED ALL-ROUND EXPERIENCE

3,850 sqm	149	96	45.7 sqm	81 sqm	15
Total plot area of the service apartment tower	Total apartments to be built	Number of studio apartments	Area of studio apartments	Area of 1bhk flats	Number of floors in the apartment tower

10,000 sqm
Built-up area of tower (668 sqm per floor)

Common amenities

Gymnasium, Yoga room, Canteen, Lounge area, Gaming zone

Laundry room, Terrace garden, Dining area and kitchen, Top-floor sitting lounge

Studio apartments at commuters' service

- NCRTC is constructing studio apartments near its upcoming Jangpura RRTS station and stabling yard
- The apartments will be fully furnished and services like housekeeping, kitchen, laundry, etc, will be part of the rent
- The apartments will be meant for short stays; NCRTC is going to engage a 'serviced apartment operator' to maintain them and provide services
- The serviced apartments are being built under Transit-Oriented Development (TOD) as Jangpura has been identified as a transit node

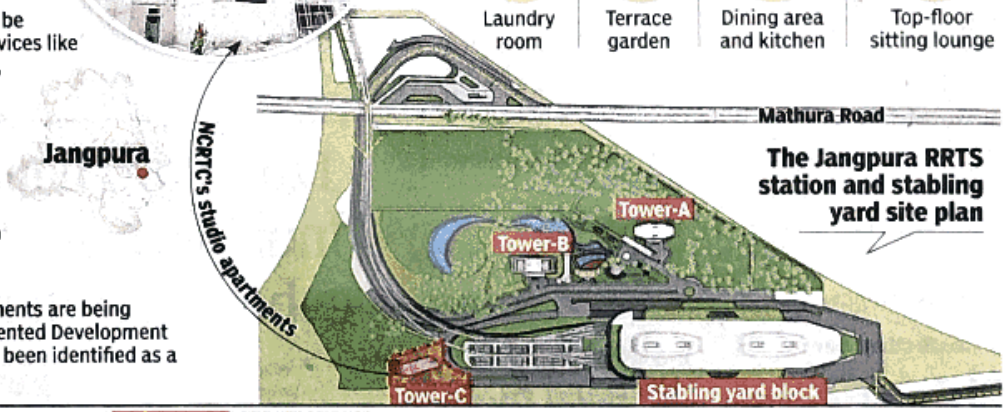

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED-- नई दिल्ली, मंगलवार 20 सितंबर, 2022

नई दिल्ली। मंगलवार • 20 सितम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

लंबित योजनाओं के काम में तेजी लाएं : एलजी

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी के 77 कॉरिडोर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए चल रही योजनाओं को उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समीक्षा की। बैठक में उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि 620 में 334 कार्य पूरे हो चुके हैं।

देरी से चल रही योजनाओं पर जताई नाराजगी

उन्होंने उम्मीद जतायी है कि 4 जुलाई के बाद पूरी हुई योजनाओं से मोतीबाग,आरटीआर, न्यू रोहतक रोड, पुराना पटपड़गंज रोड, लोनी रोड आदि पर यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने देरी से चल रही योजनाओं पर नाराजगी जताई। बैठक में मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष डीडीए, विशेष पुलिस आयुक्त, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, गृह विभाग, दिल्ली पुलिस, डीयूएसआईबी के अधिकारी मौजूद थे।उप-राज्यपाल ने बताया कि 4 जुलाई की समीक्षा बैठक के बाद सड़कों की मरम्मत, लोहे के ग्रिल की स्थापना, पुलों का चौड़ीकरण, कचरा डंपिंग साइट का स्थानांतरित करने जैसी योजना में अब तक 10 कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने सभी कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करने को कहा। अधिकारियों ने उन योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें जमीन संबंधी समस्या ओड़े आ रही है। अधिकारियों ने दिल्ली गेट से कमल टी प्वाइंट तक एलिवेटिड कॉरिडोर के लिए लंबित मंजूरी का भी मामला उठाया। जिन कार्यों में अतिक्रमण आड़े आ रहा है, उसे तत्काल हटाने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि 44 दीर्घकालिक कार्यों और 25 अल्पकालिक कार्य समेत कुल 109 कार्य अभी भी लंबित है। उप-राज्यपाल ने अधिकारियों को इन कार्यों में आ रही अड़चनों के समाधान का रास्ता निकालने को कहा।

उप-राज्यपाल ने अधिकारियों बिजली के खंभों एवं 5 ट्रांसफार्मरों का स्थानांतरित करने, पेड़ों को हटाने से संबंधित कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सभी यातायात क्षेत्रों में टास्क फोर्स गठित किए गए थे। टास्क फोर्स की टीमों ने यातायात में सुधार के लिए लगभग 400 किलोमीटर के 77 कॉरिडोर की पहचान की थी।

दैनिक भास्कर

प्रगति और लंबित कार्यों की समीक्षा की

एलजी ने सड़कों से कब्जा हटाने का निर्देश दिया

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

इन 77 कॉरीडोर में से 334 पर हो चुके हैं काम

अधिकारियों ने एलजी को बताया कि इन 77 कॉरिडोर पर 620 कार्यों में से 334 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 44 दीर्घकालिक कार्यों और 25 अल्पकालिक कार्यों सहित 109 कार्य अभी भी लंबित हैं। कम से कम 119 परियोजनाओं को संभव नहीं बताया गया, जिसके लिए एलजी ने अधिकारियों से वैकल्पिक उपाय तलाशने को कहा।

दिल्ली के सड़कों पर भीड़-भाड़ खत्म करने के लिए उपराज्यपाल ने कवायद शुरू कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में 77 चिह्नित गलियारों में भीड़भाड़ कम करने से संबंधित कार्यों की प्रगति और लंबित कार्यों की समीक्षा की और समय सीमा का पालन करने के सख्त निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार वीसी-डीडीए मनीष गुप्ता, एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती, विशेष पुलिस आयुक्त और एचओडी और पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, वन विभाग, गृह विभाग, डीयूएसआईबी और डीडीए जैसी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उपराज्यपाल ने 2019 के बाद से कई कार्यों के लंबित होने पर अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही पर नाराजगी भी व्यक्त की। उपराज्यपाल ने कहा इस मुद्दे पर 4 जुलाई 2022 को हुई बैठक के बाद से, सड़कों की मरम्मत, लोहे की ग्रिल लगाने, पुल का चौड़ा करने आदि से जुड़े 10 कार्य पूरे हो चुके हैं।

उपराज्यपाल को अधिकारियों ने 'अल्पकालिक' लंबित कार्यों और 'दीर्घकालिक' लंबित कार्यों के लिए एक ठोस कार्य योजना के संबंध में विशिष्ट समय-सीमा प्रदान करने के निर्देश भी जारी किया। लंबे समय से लंबित कार्यों में सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण, बस टर्मिनलों को हटाना, प्रमुख सड़कों के किनारे नए पार्किंग स्थल बनाना, बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, एफओबी और अंडरपास का निर्माण और कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि की अनुपलब्धता शामिल है।

अधिकारियों ने एलजी को यह भी बताया गया कि दिल्ली गेट से कमल टी-प्वाइंट तक एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए मंजूरी लंबित है जो कि ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। अधिकारियों ने कार्य में देरी का कारण बताते हुए कहा कि प्रमुख सड़कों पर रास्ते के अधिकार पर कई अतिक्रमण मौजूद थे। जिसके बाद एलजी ने पीडब्ल्यूडी को विशेषकर मुख्य सड़कों से सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, ताकि इन हिस्सों को कम किया जा सके।

पंजाब केसरी

एलजी ने भीड़भाड़ कम करने के प्रोजेक्ट की समीक्षा की

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को राजधानी में 77 चिन्हित कॉरिडोर में भीड़भाड़ कम करने से संबंधित कार्यों की प्रगति की। इस दौरान उन्होंने 2019 के बाद से लंबित पड़े कई कामों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को शॉर्ट टर्म पेंडिंग वर्क और लांग टर्म के लंबित कामों के लिए एक ठोस वर्क प्लान के संबंध में विशिष्ट समय-सीमा देने के निर्देश जारी किए। लंबे समय से लंबित कार्यों में सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण, बस टर्मिनलों को हटाना, प्रमुख सड़कों के किनारे नए पार्किंग स्थल बनाना, बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, एफओबी और अंडरपास का निर्माण और कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि की अनुपलब्धता आदि शामिल हैं।

620 में से केवल 334 कार्य ही हुए पूरे

एलजी को बताया गया कि 77 कॉरिडोर पर 620 कार्यों में से 334 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 44 दीर्घकालिक कार्यों और 25 अल्पकालिक कार्यों सहित 109 कार्य अभी लंबित हैं। इनमें से कम से कम 119 प्रोजेक्ट को संभव नहीं बताया गया, जिसके लिए एलजी ने अधिकारियों से वैकल्पिक उपाय तलाशने को कहा। वहीं अधिकारियों ने बिजली के खंभों व ट्रांसफार्मरों को शिफ्ट करने व हटाने से संबंधित पांच कार्य और पेड़ों को हटाने से संबंधित सात कार्य लंबित हैं।

अधिकारियों द्वारा एलजी को बताया गया कि गत 4 जुलाई 2022 को हुई पिछली बैठक के बाद से सड़कों की मरम्मत, लोहे की ग्रिल लगाने , पुल को चौड़ा करने, कचरा डंपिंग साइट को स्थानांतरित करने और पेड़ों, बिजली और टेलीफोन के खंभों को हटाने आदि से जुड़े 10 काम पूरे किए जा चुके हैं। इससे मोती बाग आरटीआर, न्यू रोहतक रोड, पुराना पटपड़गंज रोड, लोनी रोड, बाबरपुर रोड, पुराना गुरुग्राम रोड और बिजवासन-नजफगढ़ रोड पर ट्रैफिक मूमेंट बेहतर होने की उम्मीद है। एलजी को यह भी बताया गया कि दिल्ली गेट से कमल टी-प्वाइंट तक एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए मंजूरी लंबित है जो कि ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। जब एलजी को बताया गया कि प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण मौजूद तो इस पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी को सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। इस बैठक में मुख्यसचिव, डीडीए वीसी, विशेष पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त और एमसीडी एचओडी सहित कई एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला ----------DATED 20/09/2022

काम की रफ्तार में तेजी लाए पीडब्ल्यूडी

लंबित कार्यों पर एलजी ने जताई नाराजगी, कहा-समय पर काम पूरा करने के लिए तैयार करें कार्य योजना

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली में चिन्हित 77 कॉरिडोर पर भीड़भाड़ कम करने संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। 2019 के बाद से लंबित कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एलजी ने पीडब्ल्यूडी को काम को समय सीमा के अंदर पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए।

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले हुई बैठक के बाद से सड़कों की मरम्मत, लोहे की ग्रिल लगाने, पुल का चौड़ीकरण, कचरा डंपिंग साइट, पेड़, बिजली और टेलीफोन के खंभों को हटाने सहित 10 कार्य पूरे हो चुके हैं। मोती बाग, आरटीआर, न्यू रोहतक रोड, पुराना पटपड़गंज रोड, लोनी रोड, बाबरपुर रोड, पुराना गुड़गांव रोड और बिजवासन-नजफगढ़ रोड पर ट्रैफिक बेहतर होने की उम्मीद थी। एलजी ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को नियत समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

लंबित कार्यों में सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण, बस टर्मिनल को हटाना, प्रमुख सड़कों के किनारे नए पार्किंग स्थल बनाना, बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, फुटओवर ब्रिज (एफओबी) और अंडरपास का निर्माण और कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि की अनुपलब्धता शामिल है। ब्यूरो

मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

प्रमुख सड़कों के रास्ते में अतिक्रमण पर सख्ती करते हुए एलजी ने पीडब्ल्यूडी को सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। खासतौर पर मुख्य सड़कों से, ताकि अतिक्रमण हटाने से वाहनों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी रह सके। बैठक में मुख्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष, विशेष पुलिस आयुक्त, आयुक्त, एमसीडी और एचओडी और पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, वन विभाग, गृह विभाग, दिल्ली पुलिस, डीयूएसआईबी सहित दूसरी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

119 परियोजनाओं का विकल्प तलाशें अधिकारी

एलजी को बताया गया कि 77 कॉरिडोर पर 620 कार्यों में से 334 कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्यों में 44 दीर्घकालिक, 25 अल्पकालिक कार्यों समेत 109 अन्य कार्य अभी भी लंबित हैं। इस दौरान करीब 119 परियोजनाओं को अधिकारियों ने संभव नहीं होने की जानकारी दी। एलजी ने इन कार्यों के लिए विकल्प तलाशने को कहा। बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर को हटाने संबंधी लंबित कार्यों को एलजी ने 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया।

प्रत्येक ट्रैफिक रेंज के लिए टास्क फोर्स गठित

यातायात में सुधार के लिए प्रमुख यात्रा गलियारों के निर्माण के लिए 2017 में प्रत्येक ट्रैफिक रेंज के लिए टास्क फोर्स गठित की गईं। टास्क फोर्स ने यातायात प्रबंधन के लिहाज से करीब 400 किलोमीटर के दायरे में 77 कॉरिडोर की पहचान की थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रोड इंजीनियरिंग, यातायात पुलिस की तैनाती, मौजूदा प्रणाली में बदलाव, व्यस्त समय के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ निरंतर कार्रवाई और कॉरिडोर से अतिक्रमण हटाने की दिशा में कार्य करने की पहल की गई।

---

the pioneer
NEW DELHI | TUESDAY | SEPTEMBER 20, 2022

L-G reviews work on decongestion of 77 corridors

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Reviewing the progress of work on the decongestion of 77 corridors, Lieutenant-Governor (L-G) VK Saxena on Monday directed the Public Works Department (PWD) to remove encroachments from public land, particularly areas along arterial roads so as to ensure smooth flow of traffic.

During the meeting, officials informed the L-G that out of the 620 tasks on these 77 corridors, 334 tasks have been completed while 109 including 44 long-term tasks and 25 short-term ones were pending.

According to officials, 119 projects were reported unfeasible and the L-G asked them to explore alternative measures.

Officials informed the L-G that five tasks pertaining to shifting/removal of electricity poles and transformers and seven tasks related to removal

of trees were pending and he directed them to complete these works by September 30. Officials told the L-G that since the last meeting on July 4, ten tasks involving recarpeting of roads, installation of iron grills, widening of bridges, shifting of garbage dumping sites and removal of trees, electricity and telephone poles, etc. had been completed.

"With this traffic flow was expected to be better on Moti Bagh RTR, New Rohtak Road, old Patparganj Road, Loni Road, Babarpur Road, old Gurgaon Road and Bijwasan – Najafgarh Road," officials said. "The L-G directed officials to provide specific timelines with regards to short-term pending works and a concrete action plan for the long-term ones, which includes construction and widening of roads, removal of bus terminals, creating new parking spaces along major roads, construction of multi-level parking lots, construction of foot over bridges, underpasses and unavailability of land for certain projects among others," officials said.

"Upon being informed that there were many encroachments on Right of Way on major roads, Saxena directed the PWD to remove encroachments from the public land particularly those along arterial roads so as to decongest these stretches and ensure smooth flow of traffic," officials said. Task Force teams for each traffic range were created in January 2017 with an objective to act on major travel corridors in consultation with all stakeholders to improve traffic flow. The Task Force teams had identified 77 corridors of around 400 KMs for improvement.

The tasks identified for this purpose comprise of road engineering interventions to address choke points, regulation through augmented traffic police deployment and systems, manual intervention during peak hours etc.

The meeting was attended by Chief Secretary Naresh Kumar, Vice-Chairman of the Delhi Development Authority Manish Kumar Gupta and representatives from agencies like PWD, Municipal Corporation of Delhi, Forest Department, Home Department, Delhi Police and Delhi Urban Shelter Improvement Board among others.